एन.सी.टी. राज्य दिल्ली

बनाम

अजय कुमार त्यागी

(आपराधिक अपील संख्या 1334, 2012)

31 अगस्त 2012

[आर.एम. लोढ़ा, चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही - सामान आरोपों पर विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई - जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि आरोप साबित नहीं हुए - आपराधिक मामला लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थगित रखी गई - उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में कहा कि विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना उचित था - धारा 482 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चूँकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोपी को बरी कर दिया गया है, आपराधिक कार्यवाही रद्द करने योग्य है - अपील में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस सवाल को बड़ी बेंच के पास भेज दिया कि क्या विभागीय कार्यवाही में आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिए जाने पर

आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी - बड़ी बेंच ने कहा: आपराधिक कार्यवाही को उच्च न्यायालय ने गलती से रद्द कर दिया था क्योंकि आरोपी को नहीं कहा जा सकता है। विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अभी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है - इसके अलावा, विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति वास्तव में आपराधिक अभियोजन को रद्द नहीं करेगी - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 7/13 - सेवा कानून - अनुशासनात्मक कार्यवाही। अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति के लिए, प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया गया, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई।

जांच अधिकारी ने विभागीय जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में पाया कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य की कमी के कारण आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। आपराधिक मामला लंबित होने के कारण रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी । प्रतिवादी-अभियुक्त ने पहले रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय से विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना अनुचित नहीं है।

इसके बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत

एक याचिका दायर कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की। इस आधार पर कि चूंकि अभियुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था, आपराधिक कार्यवाही केवल उसी आधार पर रद्द की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने आरोपी को इस शर्त पर आरोपों से मुक्त कर दिया कि यदि अपीलीय अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत कोई आदेश पारित किया, तो मामला फिर से खोला जाएगा। राज्य ने इस न्यायालय में अपील दायर की। इस अदालत की खंडपीठ ने इस सवाल पर कि क्या किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही में समान आरोप पर दोषमुक्ति के बावजूद जारी रह सकती है, इस अदालत की दो खंडपीठों के फैसले में विरोधाभास पाते हुए मामले को तीन न्यायाधीशों के पास भेज दिया। इस न्यायालय की खंडपीठ. अपीलकर्ता-राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की यह धारणा कि आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था, तथ्यों के आधार पर निराधार थी क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम फैसला नहीं थी और उस पर अनुशासनात्मक द्वारा अभी भी विचार नहीं किया गया था।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि:

1. उच्च न्यायालय का आदेश तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर टिकाऊ नहीं है। हालांकि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और पाया है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से बाध्य नहीं है और असहमति के लिए एक अस्थायी कारण देने और दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, निष्कर्ष से भिन्न हो सकता है और अपराध का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और दंडित कर सकता है। अपराधी कर्मचारी. वर्तमान मामले में, उक्त चरण तक पहुंचने से पहले, आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया। आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए और उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने में गलती की कि आरोपी को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया है। चूँकि उच्च न्यायालय का आदेश ग़लत आधार पर आधारित है, इसलिए उसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चूंकि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त है, इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए, इसलिए उस पर स्थापित अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किया जाना चाहिए और, उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में, विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। पुनः खोला जाए और आपराधिक मामले के समापन तक स्थगित रखा जाए। [पैरा 28, 14 और 16] [224-एफ; 217-बी-डी; 217-जी-एच; 218-ए]

2.1. पी.एस. के मामले में निर्णय राज्य में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही में किसी कर्मचारी को दोषमुक्त करने पर समान आरोप या साक्ष्य पर आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया जाए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निर्णय इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि उससे क्या निकलता है। मात्र तथ्य यह है कि पी.एस. में. राज्य इस न्यायालय ने अभियोजन को तब रद्द कर दिया जब विभागीय कार्यवाही में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस आधार पर इसे रद्द कर दिया गया था। निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के आधार पर नहीं बल्कि इसके विशिष्ट तथ्यों पर समाप्त किया गया था। [पैरा 22 और 23] [220-एच; 221-ए-बी, जी]

2.2. उच्च न्यायालय ने पी.एस. के मामले में फैसले को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ने पर अभियोजन को रद्द कर दिया। राज्य*.विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति से वास्तव में किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति या दोषमुक्ति नहीं होगी। यह सर्वविदित है कि विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक आपराधिक अभियोजन की तुलना में कम है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि विभागीय कार्यवाही या उस मामले के लिए आपराधिक मामलों का निर्णय केवल उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में सबूतों की सत्यता का आकलन उसमें सबूत पेश होने के बाद ही किया जा सकता है और

विभागीय कार्यवाही में सबूतों या उस सबूत के आधार पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26] [223-एच; 224-ए-सी]

2.3. विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति का परिणाम वास्तव में आपराधिक मुकदमा रद्द नहीं होगा। हालाँकि, यदि किसी अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पूरी तरह से कार्यवाही के निष्कर्ष पर आधारित है और उस निष्कर्ष को पदानुक्रम में वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अलग रखा गया है, तो आधार ही खत्म हो जाता है और अभियोजन को रद्द किया जा सकता है। लेकिन वह सिद्धांत विभागीय कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा वे समान पदानुक्रम में नहीं हैं। (पैरा 27] [224-डी-एफ]

राज्य बनाम एम. कृष्ण मोहन (2007) 14 एससीसी 667: 2007 (11) एससीआर 570; अधीक्षक. पुलिस (सी.बी.आई.) बनाम दीपक चौधरी(1995) 6 एससीसी 225:1995 (2) पूरक। एससीआर 818; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम वी.के. भुटियानी (2009) 10 एससीसी 674- पर भरोसा। पी.एस. राज्य बनाम बिहार राज्य 1996 (9) एससीसी 1: 1996 (2) आपूर्ति. एससीआर 631 - प्रतिष्ठित।

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 सप्लिमेंट (1)

एससीसी335:1990 (3) पूरक। एससीआर 259 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1990 (3) सप्ल. एससीआर 259 - संदर्भित - पैरा 20

1996 (2) सप्ल. एससीआर 631 - विशिष्ट - पैरा 22

2007 (11) एससीआर 570 - पैरा 24 पर निर्भर

1995 (2) सप्ल. एससीआर 818 - पर भरोसा - पैरा 24

(2009) 10 एससीसी 674 - पैरा 25 पर निर्भर

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1334/2012

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 25.8.2008 के निर्णय एवं आदेश से सी.आर.एल. एमसी नंबर 1833/2007।

जे.एस. अपीलकर्ता के लिए अत्री, अंजनी अय्यागरी, गार्गी खन्ना, बी.वी. बलराम दास।

प्रतिवादी की ओर से चेतन शर्मा, बाके बिहारी शर्मा (आशा गोपालन नायर के लिए)।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद द्वारा सुनाया गया:

1. अजय कुमार त्यागी, प्रासंगिक समय पर, दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल सुरिंदर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर पानी के कनेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड, जिसे इसके बाद 'बोर्ड' कहा जाएगा, में आवेदन किया।शीला देवी. जल कनेक्शन देने के आवेदन को सहायक अभियंता द्वारा मंजूरी दे दी गई और फाइल उक्त अजय कुमार त्यागी (इसके बाद 'आरोपी' के रूप में संदर्भित) को भेज दी गई।

2. कांस्टेबल सुरिंदर सिंह ने एंटी करप्शन ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। 2000/- फ़ाइल को साफ़ करने के लिए और रु. शुरुआत में 1000/- रुपये का भुगतान किया जाना था और शेष राशि फ़ाइल की मंजूरी के बाद दी जानी थी। दर्ज की गई जानकारी के आधार पर, एक जाल बिछाया गया और अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने रुपये की रिश्वत की मांग की और स्वीकार किया। 1000/-. इसके चलते भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

3. जांच के बाद 19 सितंबर 2002 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और आरोपी पर मुकदमा चलाया गया. विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किये गये.

4. इसी घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही

भी शुरू की गई और उस पर आरोप की धारा तामील की गई। विभागीय कार्यवाही में यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने "एक लोक सेवक होते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन भ्रष्ट और अवैध तरीकों से या अन्यथा किया, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, 1000/- (एक हजार) रुपये की मांग की, स्वीकार की और प्राप्त की। जल कनेक्शन पर एक रिपोर्ट देने के लिए श्री सुरिंदर सिंह पुत्र श्री राम भजन निवासी मकान नंबर 432-ए, गली नंबर 2, 80 वर्ग गज, ग्राम मंडोली, दिल्ली से कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि

5. जाँच अधिकारी ने विभागीय जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच अधिकारी ने पाया कि "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप को साबित नहीं करते हैं" और तदनुसार, यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि रिकॉर्ड पर सबूत की कमी के कारण आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण जांच अधिकारी। तदनुसार, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही के समापन की प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। अभियुक्त द्वारा की गई दलील को उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला और 2 फरवरी, 2007 के फैसले और आदेश द्वारा, अन्य

बातों के साथ-साथ रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया:

> "इसलिए, मुझे विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने में प्रतिवादियों की कार्रवाई किसी भी तरह से अनुचित नहीं लगती, खासकर तब जब याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के बावजूद उसे सेवा से निलंबित नहीं किया गया है और वह लगातार उसके कर्तव्य. का प्रदर्शन कर रहा है।"

7. इसके बाद, आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक अन्य उपाय का सहारा लिया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत उसके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना की। प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना इस आधार पर की गई थी कि चूंकि आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक विस्तृत आदेश द्वारा बरी कर दिया गया है, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उसी आधार पर रद्द करने योग्य है। पी.एस. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। राज्य बनाम बिहार राज्य [1996 (9) एससीसी 1]।

8. उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोप और विभागीय कार्यवाही का हवाला दिया और कहा कि "इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि दोनों कार्यवाही में लगाए गए आरोप समान हैं"। तदनुसार,

उसने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और ऐसा करते समय, निम्नानुसार देखा गया:

> "उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि यदि विभागीय कार्यवाही उन आरोपों के संबंध में अभियुक्तों के पक्ष में निष्कर्ष पर समाप्त होती है जो आपराधिक कार्यवाही का आधार बनते हैं तो विभागीय निर्णय आपराधिक कार्यवाही का आधार ही ख़त्म कर देगा और ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना एक निरर्थक अभ्यास और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मुझे लगता है कि वर्तमान मामले में आरोप उन्हीं आरोपों पर आधारित है जो जल बोर्ड के जांच अधिकारी के समक्ष विचाराधीन थे। यदि विभागीय कार्यवाही में आरोप साबित नहीं किया जा सका, जहां सबूत का मानक बहुत कम था, तो यह बहुत कम संभावना है कि वही आरोप आपराधिक मुकदमे में साबित किया जा सके, जहां सबूत का मानक तुलनात्मक रूप से काफी सख्त है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर आपराधिक कार्यवाही चलाने का परिणाम केवल उसका उत्पीड़न होगा।"

9. इससे व्यथित होकर, राज्य ने यह विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

अनुमति दी गई.

10. यहां यह बताना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने, 25 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा, आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया, "इस शर्त के अधीन कि यदि कोई अपील दायर की जाती है राज्य द्वारा और 25.08.2008 के आक्षेपित उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत एक आदेश प्राप्त होता है, मामले को फिर से खोला जाएग' अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और केवल उसी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था।

11. जब मामला विचारार्थ आया तो 13 सितंबर, 2010 को इस न्यायालय की खंडपीठ ने, इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के बीच विरोधाभास पाते हुए, इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेजा और ऐसा करते समय, इस प्रकार टिप्पणी की:

> "मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है और उसे एक ट्रैप मामले में पकड़ा गया है। हम विवाद के गुण-दोष पर नहीं जा रहे

हैं।"हालाँकि, ऐसा लगता है कि दो परस्पर विरोधी निर्णय हैं इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठों में से; (i) पी.एस. राज्य बनाम.बिहार राज्य ने (1996) 9 एससीसी 1 में रिपोर्ट दी, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि यदि किसी व्यक्ति को विभागीय कार्यवाही में बरी कर दिया जाता है, तो उसी विषय पर उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है या जारी नहीं रखी जा सकती है, (आईएल) किशन सिंह Lrs के माध्यम से. बनाम गुरपाल सिंह और अन्य 2010 (8) स्केल 205, जहां अन्य दो जजों की बेंच ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। हम बाद वाले दृष्टिकोण से सहमत होने के इच्छुक हैं क्योंकि अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध है। एक आपराधिक मामले की सुनवाई एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो कानून में प्रशिक्षित है, जबकि विभागीय कार्यवाही आमतौर पर विभाग के एक अधिकारी द्वारा की जाती है जो कानून में अप्रशिक्षित हो सकता है।हालाँकि, हम इस मामले में कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इन परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए, हमारी राय है कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।"

मामला इस तरह हमारे सामने है.

12. श्री जे.एस. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अत्तरी का कहना है कि यह धारणा, जिस पर उच्च न्यायालय आगे बढ़ा था, कि आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी कर दिया गया है, तथ्यों पर निराधार है। वह बताते हैं कि जांच अधिकारी ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया था और पाया कि आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी बरी कर दिया गया है। वह बताते हैं कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है और किसी भी चीज ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आरोपी को दंडित करने से नहीं रोका है। केवल इस आधार पर उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाना उचित है, ऐसा श्री अत्री का कहना है।

13. हालांकि, प्रतिवादी-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चेतन शर्मा का कहना है कि इतने समय की दूरी पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कोई भी निर्णय पारित करने से रोक दिया जाता है।आदेश और अनुशासनात्मक कार्यवाही को दोषमुक्ति के साथ समाप्त माना जाएगा।

14. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना ध्यान दिया है और हमें श्री अत्तरी की प्रस्तुति में तथ्य नजर आता है। यह सच है कि जांच अधिकारी

ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और पाया है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से बाध्य नहीं है और असहमति के लिए एक अस्थायी कारण देने और दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, निष्कर्ष से भिन्न हो सकता है और अपराध का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और दंडित कर सकता है। अपराधी कर्मचारी. वर्तमान मामले में, उक्त चरण तक पहुंचने से पहले, आरोपी ने आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उक्त कार्यवाही को रद्द करने में गलती की कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त किया गया। चूँकि उच्च न्यायालय का आदेश ग़लत आधार पर आधारित है, इसलिए उसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

15. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विभागीय कार्यवाही के समापन की मांग करते हुए आरोपी द्वारा दायर की गई रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक मामले की लंबितता तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना अनुचित नहीं है, और वह आदेश अंतिम रूप ले चुका है. इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोपी को आरोपों से मुक्त करने का दिनांक 25 मार्च, 2009 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आधार पर

स्थापित किया गया है और उसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यदि कोई आदेश इसके विपरीत हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ तो मामले को दोबारा खोला जाएगा।

16. जैसा कि हमने यह विचार किया है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त है, उसे रद्द किया जाना चाहिए, इसलिए उस पर स्थापित अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किया जाना चाहिए और, निर्देश के आलोक में उच्च न्यायालय, विभागीय कार्यवाही को फिर से खोला जाना चाहिए और आपराधिक मामले के समापन तक स्थगित रखा जाना चाहिए।

17. अब हम हमारे सामने आए कानून के प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्या विभागीय कार्यवाही में समान आरोप पर दोषमुक्ति के बावजूद किसी आरोपी के खिलाफ अभियोजन जारी रह सकता है या नहीं!

18. श्री शर्मा दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि इस प्रश्न का निपटारा पी.एस. राज्य (सुप्रा), के मामले में इस न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। परंतु जिसने 1996 से इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, इसलिए समय की इतनी दूरी पर, इसके अनुपात पर पुनर्विचार करना और उसे परेशान करना अनुचित है। हालाँकि, श्री अट्री का मानना है कि उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं माना है कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति

वास्तव में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर देगी।

19. हमने प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर गंभीरता से विचार किया है और मामले के सही अनुपात को समझने के लिए, हमने जिस फैसले पर भरोसा किया है उसे बहुत बारीकी से पढ़ा है।

इस मामले में, विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले में दोषी कर्मचारी के खिलाफ आरोप एक ही थे, यानी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का। संपत्ति के मूल्य का आकलन करने के लिए अभियोजक केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाद में दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया। इस न्यायालय ने वास्तव में पाया कि "आरोप-पत्र के आधार के रूप में दिया गया मूल्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा बाद में दी गई रिपोर्ट में दिया गया मूल्य नहीं है।" यह निर्णय के पैराग्राफ 15 के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट होगा:

> "15.....विद्वान वकील के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस पहलू पर विस्तार से विचार किया है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बाद की मूल्यांकन रिपोर्टें जिन पर सीबीआई ने भरोसा किया, वे संदिग्ध प्रकृति की हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। अन्यथा भी आरोप-पत्र के आधार के रूप में दिया गया मूल्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बाद में दी गई

रिपोर्ट में दिया गया मूल्य नहीं है।"

20. इसके बाद, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335 के मामले में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित उदाहरणों को पुनः प्रस्तुत किया। या आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां। उदाहरणों के माध्यम से मामलों की श्रेणियां, जिनमें शक्ति का प्रयोग या तो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार पढ़ें:

> "(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों

द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप कहां है इतना बेतुका और स्वाभाविक रूप से असंभव जिसके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट

कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संबंधित संहिता या अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

21. उपरोक्त दृष्टांत इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति पर, उसी आरोप या साक्ष्य पर आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि, इस न्यायालय ने उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर अभियोजन को रद्द कर दिया, यह पाते हुए कि उक्त मामले को दिशानिर्देशों में उल्लिखित एक से अधिक शीर्षकों के तहत लाया जा सकता है। यह निर्णय के पैराग्राफ 21 और 22 से स्पष्ट होगा, जो इस प्रकार है:

21. वर्तमान मामले को बिना किसी कठिनाई के ऊपर दिए गए एक से अधिक शीर्षकों के अंतर्गत लाया जा सकता है।

22. उपरोक्त चर्चा इस मामले के तथ्यों पर इस अपील की अनुमति

देने के लिए पर्याप्त है

22. दोहराव की कीमत पर भी, हम पी.एस. राज्य (सुप्रा) के मामले में कोई भी शीर्ष जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करते। समान आरोप पर आपराधिक अभियोजन पर विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के प्रभाव के संबंध में है। पी.एस. राज्य (सुप्रा) के मामले में निर्णय इसलिए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं देता है कि विभागीय कार्यवाही में किसी कर्मचारी को दोषमुक्त करने पर, समान आरोप या सबूत पर आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया जाए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निर्णय इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि उससे क्या निकलता है। मात्र तथ्य यह है कि पी.एस. में. राज्य (सुप्रा), इस न्यायालय ने अभियोजन को तब रद्द कर दिया जब आरोपी को विभागीय कार्यवाही में बरी कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसे उस आधार पर रद्द कर दिया गया था। यह निर्णय के पैराग्राफ 23 से स्पष्ट होगा, जो इस प्रकार है:

23। भले ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सहित इन सभी तथ्यों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि उठाए गए मुद्दों को अंतिम कार्यवाही और रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, विभागीय कार्यवाही में अपीलकर्ता को उसी आरोप से मुक्त करने से

अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला समाप्त नहीं होगा। हमने पहले ही माना है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर दिए गए कारणों के लिए, आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है अपीलकर्ता का पीछा नहीं किया जा सकता। इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।

अपील की अनुमति देने और विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और परिणामी राहत देने के हमारे दिनांक 27-3-1996 के आदेश के यही कारण हैं।

(रेखांकित करते हुए)

23. निर्णय के उपरोक्त अंश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि इसके विशिष्ट तथ्यों पर समाप्त किया गया था।

24. यह उल्लेख करने के लायक है। पी.एस. राज्य (सुप्रा) में वह निर्णय राज्य बनाम एम. कृष्ण मोहन (2007) 14 एससीसी 667 के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था। एक समान प्रश्न का उत्तर देते समय यानी कि क्या किसी व्यक्ति को विभागीय मामले में दोषमुक्त किया गया था जांच अकेले उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही में बरी करने का हकदार होगी, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के कारण आपराधिक

मुकदमे में आरोपी को बरी नहीं किया जा सकेगा। इस न्यायालय ने पी.एस. राज्य (सुप्रा) में उस निर्णय पर ज़ोर देकर कहा। उसमें प्राप्त विशिष्ट तथ्यों पर का प्रतिपादन किया गया। इस संबंध में उक्त निर्णय के पैराग्राफ 32 और 33 को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त है:

> ""32. श्री नागेश्वर राव ने पी.एस. राज्य बनाम बिहार राज्य [1996 (9) एससीसी 1] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। तथ्य यह है कि वहां की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस मामले में, सतर्कता रिपोर्ट में, अपराधी अधिकारी को निर्दोष दिखाया गया था। उस समय, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल पर भरोसा करते हुए अनुमति दी गई थी। 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335] होल्डिंग: (पी.एस. राज्य मामला [1996 (9) एससीसी 1, एससीसी पी.9, पैरा 23)]"
>
> "23। भले ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सहित इन सभी तथ्यों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि उठाए गए मुद्दों को अंतिम कार्यवाही और रिपोर्ट में

शामिल किया जाना चाहिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, विभागीय कार्यवाही में अपीलकर्ता को उसी आरोप से मुक्त करने से अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला समाप्त नहीं होगा। हमने पहले ही माना है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर दिए गए कारणों के लिए, आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है अपीलकर्ता का पीछा नहीं किया जा सकता।"

अंततः इस न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

"33. इसलिए, उक्त निर्णय उसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह उस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी है जिसमें दोषमुक्ति दी गई है विभागीय कार्यवाही से वास्तव में आपराधिक मुकदमे में बरी होने का निर्णय हो जाएगा।"

अधीक्षक के मामले में यह बिंदु इस न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन था। पुलिस (सी.बी.आई.) बनाम दीपक चौधरी,(1995) 6 एससीसी 225, जहां दो आधारों पर रद्द करने की मांग की गई थी और आग्रह किया गया आधारों में से एक यह था कि विभागीय कार्यवाही में आरोपी को आरोप से मुक्त कर दिया गया है, अभियोजन रद्द करने के लिए

उपयुक्त है। उक्त प्रस्तुतीकरण को इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिला और उसने इसे निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया:

6. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विभागीय दोषमुक्ति का दूसरा आधार भी प्रासंगिक नहीं है। जो आवश्यक और महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्य उस अपराध का गठन करेंगे जिसके लिए मंजूरी मांगी गई है।

25. केन्द्रीय जांच ब्यूरो बनाम वी.के. भूटियानी, (2009) 10 एससीसी 674 न्यायालय का निर्णय,इस मामले में भी शामिल प्रश्न पर प्रकाश डालता है। उक्त मामले में जिस अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही चल रही थी, उसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्त ने पी.एस. राज्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अभियोजन को चुनौती दी। और उच्च न्यायालय ने अभियोजन को रद्द कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक चुनौती पर, निर्णय को उलट दिया गया और मामले में निर्णय पर भरोसा करने के बाद. कृष्ण मोहन (सुप्रा), यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन को रद्द करना अवैध था और ऐसा करते समय निम्नानुसार टिप्पणी की गई:

हमारी राय में, पी.एस. राज्य के फैसले पर उच्च न्यायालय की

निर्भरता पूरी तरह से अनुचित थी क्योंकि उस मामले में तथ्यात्मक स्थिति इस मामले में प्रचलित स्थिति से पूरी तरह से अलग थी।

26. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया के मामले में फैसले को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ने पर अभियोजन पी.एस. राज्य (सुप्रा)। वास्तव में, ऐसे उदाहरण हैं, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, स्पष्ट रूप से एक विपरीत दृष्टिकोण बताते हैं यानी विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति वास्तव में किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति या दोषमुक्ति का कारण नहीं बनेगी। सैद्धान्तिक रूप से भी यह दृष्टिकोण हमारे लिए सराहनीय है। यह सर्वविदित है कि विभाग की कार्यवाही में सबूत का मानक आपराधिक अभियोजन की तुलना में कम है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि विभागीय कार्यवाही या उस मामले के लिए आपराधिक मामलों का निर्णय केवल उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में सबूतों की सत्यता का आकलन उसमें सबूत पेश होने के बाद ही किया जा सकता है और विभागीय कार्यवाही में सबूतों या उस सबूत के आधार पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।

27. इसलिए, हमारी राय है कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति का परिणाम वास्तव में आपराधिक मुकदमा रद्द नहीं होगा। हालाँकि, हम यह

जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ अभियोजन पूरी तरह से कार्यवाही के निष्कर्ष पर आधारित है और उस निष्कर्ष को पदानुक्रम में वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अलग रखा गया है, तो आधार ही खत्म हो जाता है और अभियोजन को रद्द किया जा सकता है। लेकिन वह सिद्धांत विभागीय कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा वे समान पदानुक्रम में नहीं हैं।

28. ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय का आदेश तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर टिकाऊ नहीं है।

29. अभियुक्त को आज से चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा। चूंकि आपराधिक कार्यवाही लंबे समय से लंबित है, इसलिए मुकदमे के विद्वान न्यायाधीश को इसे शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करना चाहिए और अनावश्यक और अनावश्यक स्थगन से बचना चाहिए।

30. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के आदेश को उपरोक्त निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है।

के.के.टी.

अपील की अनुमति दी

ARUSH TRIPATHI

RAJASTHAN JUDICIAL SERVICE

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आरुष त्रिपाठी राजस्थान न्यायिक सेवा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।